

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2021—पौष 10, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 5-3/2018/1(एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 29 जुलाई, 2021 से 11 अगस्त, 2021 तक (14 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 04-325/2005/गृह-सी.—प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व के आदेश क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005 दिनांक 02-09-2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि अधिनियम के अधीन कर्तव्य या शक्ति का प्रयोग या निर्वहन नीचे उल्लेखित विषयों के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा अर्थात् :—

- (1) (क) धारा 7, धारा 8, धारा 13, धारा 15 की उप धारा (2) एवं धारा 16 के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं निर्वहन पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता शाखा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा भी किया जावेगा.
- (ख) धारा 16 के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं निर्वहन सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किया जायेगा.
- (2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने के तुरन्त पश्चात् गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा संबंधित जिला (जिलों) के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को नियंत्रक प्राधिकारी, मंत्रालय, रायपुर द्वारा सूचना दी जायेगी.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा उक्त तिथि पर लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए लागू होंगे.
2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग को अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-11-21 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 18th November 2021

No. F 4-325/Home-C/2005.—In exercise of powers conferred by Section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act No. 29 of 2005), the State Government, hereby, Super imposing the Previous Order No. F-4-325/Home-c/2005, dated 02-09-2011 directs that power of function, under the Act, relating to matters mentioned below shall be performed by the following officers, namely :—

DIRECTION

In the said Act,—

- (1) (A) Powers conferred and duties imposed on the Controlling Authority under Section 7, 8, 13 Sub-section (2) of Section 15 and Section 16 shall also be exercised and performed by the Inspector General of Police, Police Headquarter, Raipur, Chhattisgarh;

- (B) Powers conferred and duties imposed on the Controlling Authority under Section 16 shall also be exercised and performed by all District Magistrates and Superintendent of Police in their respective jurisdiction.
- (2) Immediately, after granting a license under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, the Controlling Authority, Mantralaya, Raipur shall inform the Home Department, Govt. of Chhattisgarh and District Magistrates and the Superintendent of Police of the Districts concerned.
- (3) It shall come into force from the date of its publication on the Officer Gazetted and shall also be applicable to the applications pending disposal on the said date.
- (4) This Order will come in to force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBRAT SAHOO, Additional Chief Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-05/2020/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2008 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2021 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2021 से सेवा चयन श्रेणी वेतनमान पे-मैट्रिक्स स्तर-13, रुपये 1,23,100-02,15-900/- प्रदान करता है, तथा उनके नाम के सामने अंकित कॉलम-4 में उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे-2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबंद	पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबंद
2.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल (भापुसे-2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर
3.	श्रीमती मिलना कुर्रे (भापुसे-2008)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
4.	श्री कमलोचन कश्यप (भापुसे-2008)	पुलिस अधीक्षक, जिला-बीजापुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-बीजापुर
5.	श्री के. एल. ध्रुव (भापुसे-2008)	सेनानी, 2री वाहिनी, छसबल सकरी, बिलासपुर.	सेनानी, 2री वाहिनी, छसबल सकरी, बिलासपुर.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 नवम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-05/2020/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, श्री अभिषेक शांडिल्य (भापुसे-2007) एवं श्री रामगोपाल गर्ग (भापुसे-2007) को, आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2021 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2021 से सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक वेतनमान पे-मैट्रिक्स स्तर-13क, रुपये 1,31,100-02,16,600/- में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2021

क्रमांक 22/अ-82/2018-19.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बेलगहना
- (ग) नगर/ग्राम-दारसागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.951 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1ग/4	0.138
41/1ग/5	0.138
41/1ग/6	0.166
30/2	0.300
41/1थ	0.041
39	0.169
योग	0.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रतखण्डी
व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मन्त्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्रमांक/6114/वा./भू.अ./प्र.क्र./03/अ-82/2019-20.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-रविन्द्रनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.008
438	0.070
430/2	0.024
439	0.030
425	0.001
423	0.020
418	0.004
417/1	0.008
465	0.029
466	0.008
470/2	0.003
125/1	0.104
472	0.009
97	0.088
473/2	0.009
474/3	0.010
256/3	0.004
475	0.010

(1)	(2)	अनुसूची	
123	0.052	(1) भूमि का वर्णन-	
476/1	0.010	(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	
84/1	0.065	(ख) तहसील-पखांजूर	
477	0.010	(ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर	
84/2	0.146	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर	
83	0.053		
478	0.009	खसरा नम्बर	रकबा
479/2	0.008		(हेक्टेयर में)
483	0.004	(1)	(2)
480/2	0.010		
481	0.010	418/1	0.046
533	0.027	322/4	0.008
98	0.073	321	0.016
260	0.036	320/2	0.010
259	0.040	320/1	0.013
257/2	0.020	319/2	0.010
258/2	0.020	319/1	0.010
258/1	0.060	315/6	0.010
243/1	0.125	315/2	0.010
243/2	0.032	314/2	0.009
125/2	0.030	314/1	0.009
99/4	0.004	313/2	0.010
		313/1	0.010
योग	40	304	0.048
		312	0.019
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लघु जलाशय पी.व्ही. 133 के बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.		309	0.005
		273	0.057
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.		307	0.019
		306	0.021
		261/3	0.034
		263/3	0.032
		303	0.017
		289	0.083
		295	0.040
		290	0.094
उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 नवम्बर 2021		योग	25
			0.640
क्रमांक/6115/वा./भू.अ./प्र.क्र./07/अ-82/2019-20.—			
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लघु जलाशय पी.व्ही. 133 के बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,			
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.			

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/2227.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री फूलराज वर्मा, मंगलचंद घृतलहरे, श्री मो. औरंगजेब, श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी, श्री राजेंद्र कुमार साहू, श्री सत्यनारायण सोनवानी, जिला-रायपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018, दिनांक 16 अगस्त, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री फूलराज वर्मा, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री फूलराज वर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री फूलराज वर्मा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री फूलराज वर्मा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री फूलराज वर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री फूलराज वर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थी श्री फूलराज वर्मा, ग्राम-दतरेंगा, पो.-सेजबहार, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Fulraj Varma, contesting candidate of Bhartiya Bahujan Congress from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Fulraj Varma, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Fulraj Varma, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Fulraj Varma, on 13th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Sh. Fulraj Varma, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Fulraj Varma, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Fulraj Varma, resident of Vill-Datrenga, Post-Sejbahar, Chhattisgarh and the contesting candidate of Bhartiya Bahujan Congress for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मंगलचंद घृतलहरे, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मंगलचंद घृतलहरे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मंगलचंद घृतलहरे को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मंगलचंद घृतलहरे द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मंगलचंद घृतलहरे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मंगलचंद घृतलहरे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) अभ्यर्थी श्री मंगलचंद घृतलहरे, म.नं.-97, टेमरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Mangal Chand Ghritlahre, contesting candidate of Republican Party of India (A) from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Mangal Chand Ghritlahre non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Mangal Chand Ghritlahre, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Mangal Chand Ghritlahre, on 13th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Sh. Mangal Chand, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Mangal Chand Ghritlahre, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh.Mangal Chand Ghritlahre, resident of H. No. 97, Temri, Raipur, Chhattisgarh and the contesting candidate of Republican Party of India (A) for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मो. औरंगजेब, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मो. औरंगजेब को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मो. औरंगजेब को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मो. औरंगजेब द्वारा 10 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मो. औरंगजेब ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मो. औरंगजेब निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री मो. औरंगजेब, गाजीनगर, बीरगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Shri Mohammad Aurangzeb, an Independent contesting candidate from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Mohammad Aurangzeb, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Shri Mohammad Aurangzeb, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Mohammad Aurangzeb, on 10th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Shri Mohammad Aurangzeb, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Mohammad Aurangzeb, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Mohammad Aurangzeb, Gaazinagar, Birgaon, Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी द्वारा 14 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री बलदेव प्रसाद द्विवेदी, टाटीबंघ, भरकापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Baldev Prakash Dwivedi, and an Independent contesting candidate from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Baldev Prakash Dwivedi, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Baldev Prakash Dwivedi, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Baldev Prakash Dwivedi, on 14th July, 2020, Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Sh. Baldev Prakash Dwivedi, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Baldev Prakash Dwivedi, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Baldev Prakash Dwivedi, resident of Tatiband, Bharkapara, Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेंद्र कुमार साहू, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेंद्र कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेंद्र कुमार साहू को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राजेंद्र कुमार साहू द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेंद्र कुमार साहू ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेंद्र कुमार साहू निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री राजेंद्र कुमार साहू, मलसाय तालाब के पास, पीयूष नगर, कुशालपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Rajendra Kumar Sahu, and an Independent contesting candidate from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Rajendra Kumar Sahu, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Rajendra Kumar Sahu, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Rajendra Kumar Sahu, on 14th July, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Sh. Rajendra Kumar Sahu, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Rajendra Kumar Sahu, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Rajendra Kumar Sahu, resident of Vaman Rao Lakhe Ward No. 64, Near Malsay Talab, Piyush Nagar Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 16 अगस्त, 2021—25 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/48/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सत्यनारायण सोनवानी, जो छत्तीसगढ़ के 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सत्यनारायण सोनवानी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सत्यनारायण सोनवानी को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सत्यनारायण सोनवानी द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 7599/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सत्यनारायण सोनवानी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सत्यनारायण सोनवानी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 48-रायपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री सत्यनारायण सोनवानी, ग्राम-हरीभट्टा, थाना व तह. सिमगा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 16 August, 2021—25 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/48/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Raipur Rural Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Satyanarayan Sonwani, and an Independent contesting candidate from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Satyanarayan Sonwani, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, Sh. Satyanarayan Sonwani, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Satyanarayan Sonwani, on 19th May, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter 7599/निर्वा./नि.प./2020 dated 16th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 354/निर्वा./नि.प./2020/184 dated 15th July, 2020, has stated that Sh. Satyanarayan Sonwani, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Satyanarayan Sonwani, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Satyanarayan Sonwani, resident of Vill.-Haribhata, P.S. & Tehsil-Simga, Distt.-Baloda Bazar, Raipur, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 48-Raipur Rural Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.
